अमेरिका अफगान युद्ध हार चुका है

लेखक-स्टैनली जॉनी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

5 फरवरी, 2019

"अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद, तालिबान काबुल को कई तरीकों से चुनौती देने की कोशिश करेगा।"

19वीं सदी के कलाकार एलिजाबेथ बटलर द्वारा कैनवास पर एक प्रसिद्ध तैलचित्रण, प्रथम एंग्लो-अफगान युद्ध (1839-1842) की स्थायी छवि को दर्शाता है। इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के एक चिकित्सा अधिकारी विलियम ब्राइडन को दर्शाया गया है, जो 1842 में काबुल से घोड़े पर सवार होकर जलालाबाद पहुँचे थे। दोनों ब्रायडन घायल हो गए थे और उनका घोड़ा भी थका हुआ लग रहा था। ब्रायडन 16,000 सैनिकों और शिविर अनुयायियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति था जब ब्रिटिश आक्रमण के अस्त-व्यस्त होने के बाद काबुल से हट रहे थे।

एक सौ सैंतीस साल बाद, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपने क्लाइंट कम्युनिस्ट शासन के लिए सैनिकों को भेजा। सोवियत सैनिकों के अपयश के साथ जाने से पहले एक दशक बीत चुका था। और फिर से 2001 में, सोवियत संघ के बाद की एकमात्र महाशक्ति यू.एस.ने अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए सेना भेजी। अब, युद्ध के 17 साल बाद, जहाँ अमेरिका और ता. लिबान शांति के लिए सहमत हुए हैं, इतिहास को इतनी जल्दी नहीं भुला पाएंगे।

अतीत की गलतियों को दोहराते हुए

अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक कठिन स्थान रहा है, हांलाकि, इसके जटिल आदिवासी समीकरणों और इसके बीहड़ पहाड़ी इलाकों को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऐसे देश का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका भू-राजनीतिक भाग्य भूगोल द्वारा परिभाषित किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1839 में 'ग्रेट गेम' के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में सेना भेजी थी।

उन्हें डर था कि रूस अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा और भारत की सीमा पर इसका होना किसी ताज से कम नहीं होगा। उन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त की, अफगानिस्तान के अमीर, दोस्त मोहम्मद खान को पछाड़ दिया और सत्ता में अपने शाहजहाँ शाह दुर्रानी को स्थापित किया। जब आदिवासी लड़ाकों द्वारा हिंसक प्रतिरोध के मद्देनजर आक्रमण अपरिहार्य हो गया, तो मुख्य रूप से दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खान के नेतृत्व में गुट ने अंग्रेजों को वापस लेने का फैसला किया।

सोवियत ने भी वही गलती की। उन्होंने देश में इंट्रा-पार्टी तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान में सेना भेज दी। सोवियत संघ हाफिजुल्ला अमीन से सावधान था, जिसने 1978 के कम्युनिस्ट तख्तापलट के नेता नूर मोहम्मद तारकी की हत्या करने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। दिसंबर, 1979 में, लियोनिद ब्रेझनेव ने अफगानिस्तान में सेना की तैनाती की।

सोवियत ने एक और तख्तापलट किया, अमीन की हत्या की और राष्ट्रपति के रूप में मास्को के वफादार, बाबरक कर्मल को स्थापित किया। वियतनाम युद्ध में अपनी हार और 1979 की क्रांति के बाद ईरान के अपने नुकसान को देखते हुए, अमेरिकियों ने एक अवसर के रूप में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को देखा। उन्होंने मुजाहिदीन, आदिवासी योद्धाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की मद्द से कम्युनिस्ट शासन और उसके सोवियत बैकरों दोनों से लड़ रहे थे, जो मुस्लिम दुनिया को साम्यवाद के विस्तार के बारे में चिंतित थे। एक दशक बाद, सोवियत ने महसूस किया कि उनका व्यवसाय अस्थिर हो गया था और वापस खींच लिया गया था।

जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन पर हमला करने का फैसला किया, तो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू.बुश ने कहा कि 'आतंकवाद पर युद्ध' तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि वैश्विक पहुंच के हर आतंकवादी समूह को रोका और हराया नहीं जाता।' यह एक बड़ा आदेश था। अमेरिका ने तालिबान को जल्दी हरा दिया और अफगानिस्तान को अंततः राष्ट्रपति हामिद करजई के तहत एक निर्वाचित सरकार मिल गई।

लेकिन 17 साल की लड़ाई के बाद युद्ध वही 'का वही' रह गया। 2009 के बाद से, जब संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध के हताहतों का दस्तावेज बनाना शुरू किया, तो उस वक्त तक लगभग 20,000 अफगान नागरिक संघर्ष में मारे और 50,000 अन्य घायल हो जा चुके थे। युद्ध पर कुछ 877 बिलियन डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में कम से कम 2,000 सैन्य कर्मियों को खो दिया था।

एक अनवरत युद्ध

सवाल यह है कि इसके बदले में उनको मिला क्या? वर्ष 2001 में पीछे हटने वाला तालिबान वापसी की राह पर है। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि लगभग आधा अफगानिस्तान, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है, अब तालिबान द्वारा नियंत्रण में है। पूर्व में, इस्लामिक स्टेट का एक छोटा सेल अच्छी तरह से स्थापित है, वहां हाल के महीनों में कई सांप्रदायिक हमलें हुए है, जिससे सैकड़ों हजारा शिया मारे गए। सरकार पुराने भ्रष्टाचार से जूझ रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी सैनिकों को वापस घर लाना चाहते हैं। फिर भी उसने तालिबान के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 2017 में अफगानिस्तान में और अधिक सैनिकों को भेजने का फैसला किया। तब से लेकर अभी तक, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हवाई संचालन किया है, लेकिन यह तालिबान की गति को कमजोर करने में विफल रहा है।

यह समूह ग्रामीण अफगानिस्तान में लगातार जारी है और देश में कहीं भी हमले करने की क्षमता रखता है। 2014 के बाद से, अफगानिस्तान ने युद्ध में लगभग 45,000 सैनिकों को खो दिया है। बढ़ते नुकसान और संघर्ष में गतिरोध को तोड़ने में असमर्थता के साथ अमेरिकियों को लगता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य और 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के जैसे 21वीं सदी का पहला बड़ा युद्ध टिकाऊ नहीं है।

तालिबान की भूमिका

सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी? अमेरिका का कहना है कि उसे तालिबान से आश्वासन मिला है कि कोई भी समूह अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं प्रदान करेगा। यह युद्धविराम और अंतर-अफगान वार्ता के लिए भी जोर देगा। लेकिन तथ्य यह है कि अमेरिकी तालिबान को पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। तालिबान ने कहा कि यह अफगान प्रशासन से बात नहीं करेगा; यह सरकार की वैधता को स्वीकार नहीं करता है।

अमेरिकियों ने इसे स्वीकार किया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत की। अमेरिका ने भी सैद्धांतिक रूप से सैनिकों को बाहर निकालने के लिए, तालिबान की भविष्य की भूमिका पर कोई स्पष्ट समझौता किए बिना, सबसे बड़ी तालिबान की मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए कितना बेताब है, एक युद्ध जिसमें वह बुरी तरह से हार चुका है। यह बड़े पैमाने पर तालिबान द्वारा तय की गई शर्तों से बाहर होगा।

यह कहना अनुभवहीन लगेगा कि तालिबान केवल अमेरिकियों के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए 17 साल तक युद्ध लड़ा। इसने सत्ता के लिए संघर्ष किया, जो 2001 में अमेरिकी सैनिकों के आगमन के साथ हार गया। और यह निश्चित है कि एक बार अमेरिका को छोड़ने के बाद, तालिबान काबुल को एक या दूसरे तरीके से निश्चितरूप से चुनौती देगा।

GS World टीम...

अमेरिका-अफगानिस्तान युद्ध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अफगानिस्तान में पिछले 17 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- अमेरिका और तालिबान शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं।
- अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच शांति समझौते की रूपरेखा पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है।
- इसके तहत यह आतंकी संगठन अफगान धरती को आतंकियों का अड्डा नहीं बनने की गारंटी देगा।
- अफगान सरकार से तालिबान की वार्ता और संघर्ष विराम होने पर सभी अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो सकती है।

समस्या

- तालिबान ने अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक कठोर इस्लामी शरिया कानून के आधार पर शासन किया है।
- अब तालिबान का कहना है कि वह सत्ता पर एकाधिकार नहीं चाहता और वह दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा।
- लेकिन बहुत से विश्लेषकों को डर है कि नाटो सैनिकों की पूरी वापसी के बाद अफगानिस्तान की कमजोर और भ्रष्ट सरकार चरमरा कर गिर सकती है या नए गृहयुद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसमें पहले ही लाखों लोग मारे जा चुके हैं।
- पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित अफगान सरकार को अत्यंत भ्रष्ट और अक्षम माना जा रहा है। लोग सार्वजनिक सेवाओं के खस्ताहाल होने, असुरक्षा और घुसखोरी की शिकायत कर रहे हैं।
- 2001 में तालिबान सरकार को हटाए जाने के बाद महिलाओं को नई आजादियां मिली हैं, लेकिन उन पर अत्यंत अनुदारवादी समाज में अभी भी बहुत सारी रोक है।
- तालिबान शासन के खात्मे के 17 साल बाद भी अफगानिस्तान महिलाओं के लिए सबसे खराब देशों में शामिल है।

अफगानिस्तान भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- अफगानिस्तान एशिया के चौराहे पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और मध्य एशिया को पश्चिम एशिया से जोड़ता है।
- भारत का संपर्क ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से होता है। इसलिये अफगानिस्तान भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- अफगानिस्तान भू-रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और मध्य एशिया के मध्य स्थित है जो व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है।
- यह देश रणनीतिक रूप से तेल और गैस से समृद्ध मध्य-पूर्व और मध्य एशिया में स्थित है जो इसे एक महत्त्वपूर्ण भू-स्थानिक स्थिति प्रदान करता है।
- अफगानिस्तान पाइपलाइन मार्गों के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान बन जाता है। साथ ही अफगानिस्तान कीमती धातुओं और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है।

आर्थिक सहयोग

- भारत के लिये अफगानिस्तान निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। अफगानिस्तान में कई खनिज जैसे- सोना, लोहा, तांबा आदि प्रमुखता से पाए जाते हैं। भारतीय कंपनियों ने इनके खनन के लिये निवेश किया है।
- अफगानिस्तान के विभिन्न उद्योगों में 100 से अधिक कंपनियों ने निवेश किया है जिनमें कृषि, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित तापी (TAPI) (तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत) पाइपलाइन अफगानिस्तान से होकर गुजरती है। यह तुर्कमेनिस्तान से भारत में प्राकृतिक गैस के आयात किये जाने के लिये है।
- भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने संयुक्त रूप से एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस सौदे का उद्देश्य चाबहार बंदरगाह में पाकिस्तान को घेरकर अफगानिस्तान के भू-आबद्ध क्षेत्र तक पहुँच बनाने के लिये निवेश करना है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. तापी परियोजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. तापी परियोजना में केवल तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत देश शामिल है।
2. इसके द्वारा भारत तुर्कमेनिस्तान से तेल एवं गैस का आयात करेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the follwing statements-

1. Only Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India are included in TAPI project.
2. Through this, India will import oil and gas from Turkmenistan.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के पश्चात् भारत के समक्ष किन-किन चुनौतियों की उपस्थित होने की संभावनाएँ है? चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. After the return of American Army from Afghanistan, there is a probability of which challenges being created infront of India? Discuss.

(250 Words)

नोट : 4 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।